POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2016/अंक 06

मासिक प्रेषण दि. 8 जून, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जून, 2016 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राज्यपाल कल्याण सिंह को किसानों की पैरवी के लिए धन्यवाद! इस वक्त देश के 13 राज्य, 300 जिले और तीन लाख गांव सूखे की चपेट में हैं। सूखे का खमियाजा सभी को भुगतना होता है।

क्योंकि, जमीन पर जीने के लिए हवा, पानी और मिट्टी महत्वपूर्ण है। इसी पर हमारी खेती और किसान निर्भर हैं। इनकी गुणवत्ता और उपलब्धता में किसी भी तरह की गिरावट आने से उत्पादकता प्रभावित होती है। इससे आमजन पर ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर संकट छा जाता है।

ऐसे समय पर उनकी यह बात कि 'कृषि वैज्ञानिक, ब्यूरोक्रेट्स से लेकर जनप्रतिनिधि तक किसानों के गीत गाने के बजाय उनके फायदे के लिए कुछ करें' काफी वजनदार है। आजादी के बाद से जो भी सरकारें बनी, सभी ने गांवों के उत्थान, खेती और किसानों की समृद्धि की बातें खूब की। सूखे की स्थिति में किसानों को राहत पहुंचाने की कई योजनाएं भी बनीं। बावजूद इसके हम आज तक सूखे से निपटने में क्यों सक्षम नहीं हो पाए? गंभीर चिंतनीय विषय है।

दरअसल, अमूमन रूप से सूखे की समस्या को पानी की कमी से देखा जाता है। यह नहीं होता कि हर बार जल देवता हमसे नाराज रहते हों। वे कई बार हम पर दयालु भी रहते हैं। खूब पानी बरसता है, लेकिन उसे हम इतना संग्रहित व संरक्षित नहीं कर पा रहे कि सूखे की स्थिति में उत्पन्न संकट से निपटा जा सके।

इस बार मौसम विभाग ने अच्छी बरसात के संकेत दिए हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जलाशयों की खुदाई, कुएं एवं बावड़ियों का पुर्नसंरक्षण करने और भूजल पुर्नभरण जैसे काम हाथ में लिए गए हैं। केन्द्र सरकार भी जल प्रबंधन के लिए तौर-तरीके बना रही है। पानी सबका है, शहर हो या गांव जल संरक्षण के लिए सामूहिक रूप से सभी आगे आएं तभी अभियान सफल हो सकेगा।

खाद्य उत्पाद पैकेट पर कीमत व क्वालिटी का ठप्पा बड़ा रखें

सरकार ने पैकेट बंद खाद्य उत्पाद विनिर्माता कंपनियों के लिए नियम बदल दिए हैं। इसके तहत उन्हें पैकेट पर सामान की कीमत और उसकी गुणवत्ता समेत छह अनिवार्य सूचनाओं को और अधिक स्पष्टता व प्रमुखता के साथ अंकित करना होगा। यह पैकेट के सिरे और पेंदे के क्षेत्र को छोड़कर बाकी हिस्से के कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र में फैला होगा। इसका मकसद यह है कि ग्राहक इन सूचनाओं को आसानी से पढ़ सकें।

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री रामविलास पासवान ने संशोधित नये नियमों को जुलाई से लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए एक अलग से प्रकोष्ठ गठित करने का फैसला किया गया है। सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को भी मजबूत कर रही है और दैनिक आधार पर शिकायतों की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ रैंक का अधिकारी रखा जाएगा।

सेवायतन अस्पताल को भारी पड़ा इलाज में लापरवाही बरतना

सुभाष कॉलोनी, झोटवाड़ा निवासी सत्यनारायण शर्मा ने 1998 में अपनी गर्भवती पत्नी का अजमेर रोड स्थित सेवायतन अस्पताल में इलाज कराया था। अस्पताल में 13 अक्टूबर को उसे डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया। अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म देने में उनकी पत्नी की तबियत बिगड़ गई और खून की कमी हो जाने से उसकी मौत हो गई।

शर्मा ने खून की कमी होने और पूर्व से खून का इंतजाम नहीं किए जाने पर अस्पताल के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। जिला मंच ने मरीज की नाजुक स्थिति होने से पूर्व खून की व्यवस्था नहीं करने को अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और सेवा में दोष मानते हुए अस्पताल पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया।

लेकिन अस्पताल ने राज्य आयोग में अपील कर दी। राज्य आयोग ने अस्पताल को राहत देने के बजाय हर्जाना राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया। इस पर सेवायतन अस्पताल मामले को राष्ट्रीय आयोग में ले गए और अपने को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया। लेकिन राष्ट्रीय आयोग ने तथ्यों के आधार पर सेवायतन अस्पताल को दोषी पाया और हर्जाना राशि को दो लाख रुपए से बढ़ाकर साढ़े चार लाख रुपए करने का फैसला देते हुए सेवायतन अस्पताल को आदेश दिया कि वह सत्यनारायण शर्मा को उक्त राशि अदा करें।

गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन

देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय बीपीएल परिवार की महिलाओं को खाना पकाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। इसके लिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'उज्ज्वला' योजना की शुरुआत की है।

केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत तीन साल में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे पांच करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इससे महिलाओं के खाना बनाने में लगने वाले समय और श्रम की बचत के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी हो सकेगी।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

इंदिरा आवास योजना का नाम बदल कर अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। इंदिरा आवास योजना में पिछले तीन साल से प्रदेश में करीब 42 हजार आवास आधे-अधूरे पड़े हैं।

योजना में अफसरों की लापरवाही और मकान बनाने की इस लाचार रफ्तार के चलते गरीबों को समय पर मकान नहीं दिए जा सके। अब राज्य में संचालित 'ग्राम उदय से भारत उदय' अभियान के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने इन अधूरे आवासों को ग्राम सभा में तय होने वाले लक्ष्यों में जुड़वाकर पूरा कराने का फैसला किया है।

रोजगार नहीं तो अफसर होंगे जिम्मेदार

श्रमिकों की मांग दर्ज होने के बाद उनको समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराना अब मनरेगा कार्मिकों और अफसरों को भारी पड़ेगा। क्योंकि, विभागीय कार्मिकों व अफसरों की लापरवाही के चलते केन्द्र सरकार से श्रमिक मजदूरी का पैसा समय पर मिलने के बावजूद खर्च नहीं होता।

समय पर रोजगार व पैसा नहीं मिलने से श्रमिकों की मनरेगा के प्रति रुचि घट रही है। पिछले दिनों इसके लिए राज्य नरेगा विभाग को केन्द्र की फटकार भी लगी है। अब फैसला किया गया है कि मांग दर्ज होने के 15 दिन में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित कर्मचारी या अफसर के वेतन से श्रमिक मजदूरी के पैसे काटे जाएंगे।

शौचालय बने पर पानी का टोटा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2019 तक खुले में शौच जाने की व्यवस्था पूरी तरह खत्म करने की घोषणा की है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। इससे जनता की सोच बदली है और गांव-गांव व ढाणी-ढाणी में शौचालय बन गए। लेकिन इस मिशन की सफलता पर पानी की किल्लत भारी पड़ रही है।

देशभर में पानी के संकट के चलते गांवों में करीब 58 प्रतिशत शौचालयों का उपयोग ही नहीं हो रहा है। राजस्थान में पहले ही पानी की मारामारी है। गांवों की हालत तो और भी खराब है। राज्य में सिर्फ 37 फीसदी शौचालयों में ही जल उपलब्ध है। शौचालय होने के बावजूद लोग खुले में शौच करने को मजबूर है।

गांव से बाहर न जाए बारिश का पानी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अच्छी बरसात की खबर राहत देती है। लेकिन यह हमारे सामने एक मौका है और चुनौती भी। हम कोशिश करें कि बारिश का पानी गांव से बाहर न जाने पाए। बारिश का पानी बचाया जाएं।

इसके लिए गांव-गांव में जन आंदोलन चलाया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को जन सहयोग से तालाब बनाने और भूजल को रिचार्ज करने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा आज पानी की समस्या हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है और इस संकट से तभी उबर सकते हैं, जब हर व्यक्ति पानी का संरक्षण करने का संकल्प लें।

किसानों को नहीं मिली राहत

प्रदेश में पिछले एक साल में तीन फसलों पर लगातार प्रकृति की मार पड़ी। इससे किसानों की खड़ी फसलें तबाह हुई। उन्हें करीब 18 हजार 700 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।

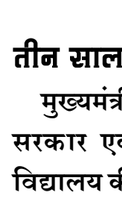

इस अवधि में प्रदेश के करीब 80 लाख से भी ज्यादा किसान फसली नुकसान से प्रभावित हुए। उनमें से मात्र 29 लाख किसानों को ही सरकारी सहायता मिल सकी है। करीब 51 लाख किसान अब भी सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं। राज्य सरकार ने 19 जिलों के करीब 15 हजार गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर रखा है, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने से किसानों की हालत ठीक नहीं है।

समूहों के उत्पाद होंगे ऑनलाइन

राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के बनाए उत्पादों को महिला ई-हाट ऑनलाइन बिक्री प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार खुद उत्पादों की जानकारी जुटाकर ऑनलाइन बिक्री के लिए सूचनाएं अपलोड करेगी। इसके लिए सभी जिलों में कार्यक्रम अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने छोटी महिला उद्यमियों के उत्पादों की बिक्री के लिए यह सेवा शुरू की है। इसका एक लिंक राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर भी होगा। इससे गांव-ढाणी में लघु उद्योगों के जरिए कमाने वाली महिलाओं को सम्बल मिल सकेगा।

तीन साल में खुलेंगे 10 हजार स्कूल

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि राज्य सरकार एक गांव, एक शिक्षक और एक विद्यालय की तर्ज पर हर ग्राम पंचायत में आदर्श विद्यालय बना रही है।

उन्होंने बताया कि आने वाले तीन सालों में 10 हजार आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ खेल व कम्प्यूटर शिक्षा भी दी जाएगी। सरकार चाहती है कि इनमें बच्चों को संस्कार और कौशल विकास की शिक्षा भी मिले। इससे गांवों में लघु उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

राजमार्गों के पास बनेंगे तालाब

केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि राजस्थान में जल संकट को देखते हुए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है। इसके तहत जहां भी राष्ट्रीय राजमार्ग का काम होगा, वहां के खेतों में किसानों की सहमति से तालाब बनाए जाएंगे। तालाब बनाने का काम केन्द्रीय राजमार्ग विभाग अपने खर्चे पर करेगा। इससे पानी का संरक्षण हो सकेगा और खेती के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा।

खातों में पड़े है रुपए

अफसोस होता है कि केन्द्र सरकार कई योजनाओं के लिए राज्य सरकार को भरपूर धन उपलब्ध कराती है, लेकिन राज्य सरकार उन योजनाओं पर पूरा धन खर्च ही नहीं कर पाती। इससे हजारों करोड़ रुपए सरकारी खातों में ही पड़े रह जाते हैं और जनता उन योजनाओं के कई फायदों से महरूम रह जाती है।

अचरज तब होता है जब भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इस बारे में जानकारी मिलती है। इनमें ग्रामीण विकास की कई योजनाएं ऐसी भी हैं जिन पर कोई काम ही नहीं हुआ और वह कागजों में ही सिमट कर रह गई। सरकार को इसके लिए क्या प्रशासन को जवाबदेह नहीं बनाना चाहिए?

-अनुराग त्रिपाठी, हनुमानगढ़

उपभोक्ता होगा ज्यादा सशक्त

देश में जल्द नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया का सरलीकरण होगा और सुनवाई के अधिकार भी बढ़ेंगे। उपभोक्ता नकली सामान दिए जाने पर कहीं से भी शिकायत दर्ज करा सकेगा। शिकायत पर हर हाल में 21 दिन में मामला दर्ज होगा, जिस पर प्राथमिकता से सुनवाई होगी।

केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री रामविलास पासवान ने यह जानकारी जयपुर में भारतीय खाद्य निगम व खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद दी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मंचों को ज्यादा अधिकार देकर सशक्त बनाया जाएगा।

गरीबों में भी गरीब खोज लाई सरकार

राजनीति में गरीब और गरीबी को लेकर भले ही आए दिन बहस हो जाती है। लेकिन, सरकार अब गरीबों में भी गरीब को ढूंढ लाई है। सरकारी आंकड़ों की माने तो प्रदेश में गरीबों में भी 1717 ऐसे परिवार हैं, जिन्होंने गरीबी की रैंकिंग में सबसे ज्यादा नम्बर लिए हैं।

इसके बाद की और भी श्रेणियां हैं, जिनमें सामाजिक और आर्थिक तौर पर एक के बाद एक निचले पायदान पर आ रहे परिवारों की रैंकिंग और संख्या तय है। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों में गरीबी मापने के लिए लगाए सूचकांकों के आधार पर यह संख्या तय की गई है। माना जा रहा है कि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबी की इसी वरीयता के आधार पर दिया जाएगा।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर